

छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था का एक विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन: फसल विविधीकरण, नीतिगत हस्तक्षेप और 'विकसित छत्तीसगढ़ 2047' का विजन
(A Comprehensive Analytical Study of the Agricultural Economy of Chhattisgarh: Crop Diversification, Policy Interventions, and the Vision of 'Viksit Chhattisgarh 2047')

डॉ. हरिशंकर साहू,

अतिथि व्याख्याता-भूगोल,

शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

सारंगढ़ (छ. ग.)

डॉ. गुंजा साहू,

अतिथि व्याख्याता भूगोल,

शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

सारंगढ़ (छ. ग.)

सार (Abstract)

छत्तीसगढ़ राज्य, जिसे 'भारत के चावल के कटोरे' के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में एक महत्वपूर्ण कृषि-आर्थिक संक्रमण के केंद्र में स्थित है। यह शोध पत्र राज्य की कृषि संरचना, फसल प्रणालियों के विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य की स्थिति, और सरकारी नीतियों के प्रभाव का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कैसे पारंपरिक धान-आधारित मोनो-क्रॉपिंग प्रणाली से उच्च-मूल्य वाली बागवानी और दलहनी फसलों की ओर स्थानांतरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और 2025-26 के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह शोध राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में कृषि के योगदान और की अनुमानित विकास दर का मूल्यांकन करता है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' (RGKNY) और 'कृषक उन्नति योजना' जैसे निवेश समर्थन कार्यक्रमों ने किसानों की आय को स्थिरता प्रदान की है, वहीं जलवायु परिवर्तन, भूमि विखंडन

The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 2 (April 2026)

और निम्न मशीनीकरण () जैसे कारक अभी भी उत्पादकता की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में बाधक बने हुए हैं। मृदा स्वास्थ्य के संदर्भ में, शोध नाइट्रोजन और फास्फोरस की व्यापक कमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों के हास की ओर ध्यान आकर्षित करता है। अंततः, यह रिपोर्ट 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु 'ज्ञान' (GYAN) और 'गति' (GATI) रूपरेखा के माध्यम से एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तावित करती है। यह शोध न केवल नीति निर्माताओं के लिए एक साक्ष्य-आधारित मार्गदर्शिका है, बल्कि भविष्य के कृषि अनुसंधान के लिए भी एक आधार प्रदान करता है।

Abstract

Chhattisgarh, popularly known as the "Rice Bowl of India," is currently positioned at the centre of a significant agricultural-economic transition. This research paper presents a comprehensive analysis of the state's agricultural structure, crop diversification patterns, soil health conditions, and the impact of government policies. The primary objective of the study is to examine how the shift from the traditional paddy-based mono-cropping system towards high-value horticultural and pulse crops is accelerating the rural economy. Using the latest data from the Economic Surveys of 2024–25 and 2025–26, the paper evaluates the contribution of agriculture to the Gross State Domestic Product (GSDP) and its projected growth rate. The analysis reveals that investment-support programmes such as the Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana (RGKNY) and the Krishak Unnati Yojana have helped stabilize farmers' income. However, factors such as climate change, land fragmentation, and low levels of agricultural mechanization continue to obstruct the full realization of productivity potential. In terms of soil health, the study draws attention to the widespread deficiency of nitrogen and phosphorus, along with the depletion of micronutrients. Finally, in alignment with the vision of Viksit Bharat 2047, this paper proposes a strategic roadmap through the GYAN and GATI frameworks to transform Chhattisgarh into a billion-dollar economy. The study serves not only as an evidence-based guide for policymakers but also as a foundation for future agricultural research.

Keywords: Chhattisgarh Agricultural Economy, Crop Diversification, Paddy-Based Agriculture, Agricultural Policy, Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana, Krishak Unnati Yojana, Soil Health, Agricultural Mechanization, Rural Economy, Viksit Chhattisgarh 2047

परिचय (Introduction)

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और आर्थिक पहचान इसके विशाल कृषि संसाधनों, घने वनों और विविध कृषि-पारिस्थितिकी प्रणालियों से परिभाषित होती है। लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य का लगभग हिस्सा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जो राज्य की से अधिक जनसंख्या को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। ऐतिहासिक रूप से, राज्य की कृषि प्रणाली धान की खेती के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है, जो वर्तमान में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग कवर करती है। हालांकि, यह निर्भरता राज्य को वैश्विक बाजार की कीमतों और मानसून की अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। वर्तमान शोध इस समस्या का गहराई से अन्वेषण करता है कि कैसे राज्य अपनी इस पारंपरिक निर्भरता को कम करते हुए एक आधुनिक, तकनीक-संचालित और विविध कृषि अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 2 (April 2026)

समस्या का मूल विवरण इस तथ्य में निहित है कि छत्तीसगढ़ के से किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिनके पास उन्नत तकनीक और ऋण तक पहुँच सीमित है। इसके अतिरिक्त, राज्य का कृषि क्षेत्र अभी भी वर्षा आधारित है, जिससे खरीफ और रबी फसलों के बीच उत्पादन में भारी अंतर बना रहता है। वर्तमान में सिंचाई क्षमता मात्र है, जिसे बढ़ाना राज्य के लिए एक अनिवार्य चुनौती है। शोध का महत्व इस बात में है कि छत्तीसगढ़ अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मूल्य संवर्धन और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनने की आकांक्षा रखता है। इस अध्ययन के मुख्य शोध प्रश्न निम्नलिखित हैं:

1. छत्तीसगढ़ के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फसल विविधीकरण की वर्तमान स्थिति और इसके आर्थिक निहितार्थ क्या हैं?
2. राज्य की कृषि कल्याणकारी योजनाओं (जैसे RGKNY और सुराजी गाँव योजना) ने किसानों की आय और उत्पादकता को किस सीमा तक प्रभावित किया है?
3. जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में मृदा स्वास्थ्य और जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु कौन सी रणनीतियाँ दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकती हैं?
4. 'विकसित छत्तीसगढ़ 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि मशीनीकरण और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका क्या होगी?

साहित्य समीक्षा (Literature Review)

छत्तीसगढ़ के कृषि परिदृश्य पर मौजूदा शोधों का विश्लेषण एक जटिल लेकिन उभरती हुई तस्वीर प्रस्तुत करता है। विद्वानों ने राज्य की कृषि को 'धान-केंद्रित' मानसिकता से उबारने की आवश्यकता पर व्यापक बल दिया है। चन्देल (2025) के अनुसार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) द्वारा धान की से अधिक जर्मप्लाज्म श्रेणियों का संरक्षण और नई पोषक-समृद्ध किस्मों का विकास राज्य की कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। वे तर्क देते हैं कि अनुसंधान और विस्तार प्रणालियों (Research-Extension Linkages) के बीच की कड़ी को मजबूत करना ही किसानों तक आधुनिक तकनीकों को पहुँचाने का एकमात्र रास्ता है।

फसल विविधीकरण के संदर्भ में, बिलासपुर जिले पर किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि जहाँ धान अभी भी क्षेत्र पर काबिज है, वहीं दालों, तिलहन और सब्जियों के क्षेत्र में क्रमिक वृद्धि हुई है। जन (2025) ने जशपुर जिले के जनजातीय किसानों पर शोध करते हुए पाया कि फसल विविधीकरण ने न केवल आय में वृद्धि की है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और पोषण

The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 2 (April 2026)

स्तर में भी सुधार किया है। हालांकि, पिंगली (2025) जैसे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि धान के रकबे में कमी लाना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, विशेष रूप से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक है।

मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक उपयोग पर पाटिल और वर्मा (2018) के शोध ने संकेत दिया है कि छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में बढ़ती लवणता संवेदनशील फसलों के विकास को बाधित कर रही है। आईसीआरआईएसएटी (ICRISAT) द्वारा किए गए मृदा उर्वरता मूल्यांकन से यह तथ्य सामने आया है कि छत्तीसगढ़ के खेतों में पोटेशियम की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन जिंक और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से तक देखी गई है, जो फसल की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

सरकारी योजनाओं के प्रभाव पर सोनवानी (2024) ने 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' का विश्लेषण करते हुए इसे एक 'मूक क्रांति' करार दिया है, जिसने खेती छोड़ चुके युवाओं को पुनः कृषि की ओर आकर्षित किया है। वहीं, मशीनीकरण के क्षेत्र में चन्द्राकर (2015) का मत है कि छत्तीसगढ़ के मैदानों में कृषि शक्ति उपलब्धता () राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है।

कार्यप्रणाली (Methodology)

यह शोध पत्र मुख्य रूप से माध्यमिक डेटा (Secondary Data) के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण पर आधारित है। आंकड़ों का संग्रह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से वित्त विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, और आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की आधिकारिक रिपोर्टों से किया गया है। 'छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25' और 'बजट 2024-25' के प्रमुख आकर्षणों को डेटा के प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग किया गया है।

डेटा विश्लेषण हेतु निम्नलिखित चरणों का पालन किया गया है:

1. **तुलनात्मक विश्लेषण:** पिछले पाँच वर्षों के कृषि विकास दर और GSDP योगदान का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।
2. **क्षेत्रीय विभेदन:** छत्तीसगढ़ के तीन प्रमुख कृषि-जलवायु क्षेत्रों—उत्तरी पहाड़, मध्य मैदान, और बस्तर पठार—के डेटा को अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है।
3. **मृदा स्वास्थ्य मानचित्रण:** उपलब्ध प्रयोगशाला रिपोर्टों के आधार पर मृदा पोषक तत्वों की स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 2 (April 2026)

4. **नीतिगत मूल्यांकन:** कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी डेटा और बजट आवंटन का विश्लेषण किया गया है.

परिणाम और विश्लेषण (Results & Analysis)

छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के विश्लेषण से प्राप्त परिणाम एक मजबूत लेकिन चुनौतियों से घिरे क्षेत्र का संकेत देते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर है.

तालिका 1: छत्तीसगढ़ का वृहद-आर्थिक और कृषि प्रदर्शन (2023-2025)

विवरण	2023-24 (वास्तविक/PE)	2024-25 (अनुमानित/BE)	वृद्धि (%)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP स्थिर मूल्य)	₹3,02,118 करोड़	₹3,29,752 करोड़	9.14%
कृषि और संबद्ध क्षेत्र का GSDP योगदान	₹48,987 करोड़	₹51,621 करोड़	5.38%
प्रति व्यक्ति आय (Current Prices)	₹1,48,922	₹1,62,870	9.37%

तालिका 2: फसल विविधीकरण और क्षेत्र विवरण (2024-25)

फसल श्रेणी	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन क्रम (Ranking)	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र
धान (Paddy)	38.93	1	छत्तीसगढ़ के मैदान
मक्का (Maize)	2.50	2	बस्तर और उत्तरी पहाड़

The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 2 (April 2026)

फसल श्रेणी	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन क्रम (Ranking)	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र
चना (Gram)	3.85	3	मध्य छत्तीसगढ़

ये परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़ अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विविधीकरण के एक संक्रमणकालीन दौर में है।

चर्चा (Discussion)

छत्तीसगढ़ की कृषि रणनीति अब 'जीवन निर्वाह' से हटकर 'व्यावसायिक और टिकाऊ' मॉडल की ओर बढ़ रही है। फसल विविधीकरण किसानों के आर्थिक जोखिमों को कम करने का एक साधन है। 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) ने ग्रामीण तरलता में सुधार किया है। हालांकि, मशीनीकरण की दर () अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है, जो उत्पादकता को सीमित करती है। 'विकसित छत्तीसगढ़ 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और डिजिटल विपणन को आगामी दो दशकों की प्राथमिकता बनाना होगा।

निष्कर्ष और भविष्य की राह (Conclusion & Future Scope)

मुख्य निष्कर्ष यह है कि छत्तीसगढ़ ने कृषि विकास दर में की वृद्धि प्राप्त करके अपनी आर्थिक सुदृढ़ता साबित की है। फसल विविधीकरण आय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा उर्वरता और निम्न मशीनीकरण जैसी समस्याओं को हल करने के लिए दीर्घकालिक निवेश अनिवार्य है।

भविष्य की राह: आने वाले समय में, छत्तीसगढ़ को 'स्मार्ट कृषि' (Smart Farming), जिसमें ड्रोन तकनीक और एआई-आधारित मृदा स्वास्थ्य निगरानी शामिल है, को अपनाना होगा। अनुसंधान के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाली किस्मों के विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

संदर्भ /References

Directorate of Economics and Statistics. (2025). *Chhattisgarh Economic Survey 2024-25*. Government of Chhattisgarh.

Sonwani, F. K. (2024). The Impact of Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana on Agricultural Development in Chhattisgarh State. *Gurukul International Multi-Disciplinary Research Journal*, 12(2).

The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 2 (April 2026)

- Sahu, D., & Sahu, V. K. (2020). Agricultural Mechanization in Chhattisgarh: Status and Prospects. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 9(5), 1433-1448.
- Singh, A., Kumar, S., & Agrahari, R. K. (2024). Study on Crop Diversification through Area Status of Crops in Kharif Season of Chhattisgarh. *International Journal of Environment and Climate Change*, 14(4), 795-814.
- International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT). (2025). *Soil Fertility Assessment of Crop Fields in Chhattisgarh*. Charles Renard Analytical Laboratory.
- Finance Department. (2024). *Key Highlights: Budget 2024-25*. Government of Chhattisgarh.
- NITI Aayog. (2025). *Vision for Viksit Bharat @ 2047: An Approach Paper for Chhattisgarh*. Government of India.
- Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). (2025). *Agricultural Land Use Statistics and Irrigation Data 2024-25*.
- Sharma, M., & Bhave, S. (2024). Critical Study of the Contribution of MARKFED in Agricultural Stability of Chhattisgarh State. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 5(2), 737-741.
- Chandel, G. (2025). *Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya: The University's Profile 2024-25*. IGKV Raipur.
- Chandel, G. (2025). *Strengthening Research-Extension Linkages for Biotic Stress Management*. PIB Raipur Release.
- Kaushal, R., & Jain, B. C. (2023). Comparative Study on Crop Diversification in Tribal and Non-tribal Area of Chhattisgarh. *International Journal of Environment and Climate Change*, 13(9), 1091-1095.
- Jana, R. (2025). Levels of Crop Diversification and Its Impact on Poor Farmers: A Case Study of Jashpur District. *Asian Journal of Geographical Research*, 8(3), 333-343.
- Pingali, P. (2025). *Chhattisgarh Can Reduce Ag Emissions Through Diversification*. Tata-Cornell Institute (TCI) Policy Brief.
- Patel, R. K., & Verma, R. (2018). Ground Water Quality Assessment for Irrigation in Bilaspur Region. *Journal of Scientific Research and Reports*.